अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह गुजराल के समक्ष

मैम राज और अन्य, अपीलकर्ता

बनाम।

दर्शन सिंह *उर्फ रंजीत सिंह* और अन्य, उत्तरदाता

1971 के आदेश संख्या 25 से दूसरी अपील

14 सितंबर, 1971

सिविल प्रक्रिया संहिता (आईएमएस *का अधिनियम V) - आदेश 41, नियम 1 और 3 - उच्च न्यायालय के नियम और आदेश, खंड V - अध्याय* 1, भाग ए (ए *),* नियम 2 (ए) - *नियम 2 (ए) में प्रदान किए गए मुद्रित फॉर्म पर अपील का ज्ञापन तैयार नहीं किया गया है और यदि ऐसा तैयार किया गया है, तो फॉर्म के सभी कॉलम नहीं भरे गए हैं - क्या आदेश 41 के तहत खारिज किया जा सकता है , नियम 3* - अपीलज्ञापन न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर संशोधित किए जाने के लिए अपीलकर्ता को लौटाया जाता है और निश्चित समय के भीतर संशोधन नहीं किया जाता है - क्या नियम 3 के तहत खारिज किया जा सकता *है - ऐसी अस्वीकृति - क्या अपील स्वीकार किए जाने के बाद हो सकती है।*

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 के नियम 1 में प्रावधान है कि प्रत्येक अपील को ज्ञापन के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस नियम

के उपनियम (2) में यह प्रावधान है कि इस तरह के ज्ञापन में क्या शामिल होना चाहिए। इस नियम में, मुद्रित प्रपत्र का कोई संदर्भ नहीं है जो उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड V द्वारा निर्धारित किया गया है, या संहिता के नंबर 1 पर परिशिष्ट जी में उल्लिखित फॉर्म का संदर्भ है, लेकिन संदर्भ केवल उस तरीके से है जिसमें ज्ञापन तैयार किया जाना है। प्रयुक्त अभिव्यक्ति "ज्ञापन के रूप में" है और ज्ञापन के "मुद्रित रूप में" या, "निर्धारित रूप" पर नहीं है। इस आदेश के नियम 3 में प्रावधान है कि अपील का ज्ञापन अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि इसे पहले निर्धारित तरीके से तैयार नहीं किया गया है। "यहां से पहले" पद आदेश 41 के नियम 1 को संदर्भित करता है जिसमें इसके उप-नियम (2) शामिल हैं। इसलिए, ज्ञापन को संहिता के आदेश 41 के नियम 3 के तहत अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मुद्रित रूप पर तैयार करने में विफल रहा है जैसा कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड V में प्रदान किया गया है, क्योंकि यह नियम द्वारा परिकल्पित नहीं है। मुद्रित फॉर्म के सभी कॉलम भरने में अपीलकर्ता की विफलता के लिए इस नियम के तहत इसे भी खारिज नहीं किया जा सकता है।

हालांकि आदेश 41 के नियम 3 में यह विशेष रूप से नहीं कहा गया है कि क्या अपील का ज्ञापन अपीलकर्ता को न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर संशोधित करने के लिए वापस कर दिया जाता है और यदि निर्धारित समय के भीतर संशोधन नहीं किया जाता है, तो अपील को अस्वीकार कर दिया जा सकता है, लेकिन यह शक्ति स्वाभाविक रूप से इस नियम से प्रवाहित होगी। यदि अपील का ज्ञापन इसे निर्धारित तरीके से तैयार नहीं किए जाने की स्थिति में पहली बार में खारिज किया जा सकता है, यदि संशोधन न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो इसे निश्चित रूप से खारिज कर दिया जा सकता है। लेकिन ज्ञापन में अस्वीकृति का दायित्व शामिल नहीं होगा

जहां अपील स्वीकार की गई है और अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किए जाने पर अस्वीकार नहीं किया गया था। अपील को नियमित सुनवाई के लिए निर्धारित करना होगा। इसलिए समय के भीतर अपील दायर की गई है और नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने के बाद नियमित सुनवाई के चरण में इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ता उप रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत समय के भीतर अपील की शुरुआती शीट में दोषों को दूर करने में विफल रहा था।

अंबाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री रघबीर सिंह गुप्ता की अदालत के दिनांक 25 नवम्बर, 1970 *के आदेश से दूसरी अपील में श्री आईपी वशिष्ठ उप-न्यायाधीश द्वितीय वर्ग, जगाधरी के* दिनांक 28 अक्तूबर, 1968 *के आदेश को पलटते हुए इन तीन अपीलों को स्वीकार करते हुए और इन तीन अपीलों में पारित डिक्री को निरस्त करते हुए मामलों को न्यायालय को सौंप दिया गया।ट्रायल कोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई की मांग की और अपीलकर्ताओं को उक्त अवधि के लिए नक्सा हकदार की प्रमाणित प्रति और फराद जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया। ऐसा किए जाने के बाद इन तीन मामलों पर नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा और अपीलकर्ताओं* का *खंडन करने और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ने के मामले में आगे के साक्ष्य जोड़ने का भी अधिकार होगा।*

अपीलकर्ताओं की ओर से *मनमोहन सिंह लिब्रहन, अधिवक्ता।*

श्री आर एन मित्तल, अधिवक्ता, *उत्तरदाताओं के लिए।*

निर्णय

न्यायमूर्ति गुजराल —(1) नायब सिंह उर्फ सिपेदार काफी जमीन का मालिक था। अपनी भूमि के एक हिस्से के संबंध में उन्होंने 4 जून, 1957 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा मामराज, सिंह राम और शादी राम के सुंदर पुत्रों के पक्ष में बिक्री की। 4 जुलाई, 1957 को एक अन्य विक्रय विलेख द्वारा उन्होंने मणि राम और कोना को कुछ अन्य भूमि बेच दी। लगभग एक महीने बाद उन्होंने 12 जुलाई, 1955 को एक पंजीकृत बिक्री-विलेख के माध्यम से शादी राम के पक्ष में एक और बिक्री की। नसीब सिंह के बेटों ने इन बिक्री को चुनौती देते हुए तीन अलग-अलग मुकदमे दायर किए, इन आरोपों पर कि भूमि पैतृक थी, कि पार्टियां रीति-रिवाजों द्वारा शासित थीं जो आवश्यकता के बिना भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती थीं और यह कि विचार और आवश्यकता के बिना की गई बिक्री शून्य थी और उनके अधिकारों के खिलाफ कोई प्रभाव नहीं था। तीनों मुकदमों के विचारण को समेकित किया गया और निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए -

1. क्या वादी विक्रेता के बेटे हैं?
2. क्या ये जमीनें वादी के पैतृक पक्ष के अनुरूप हैं? क्या वादी और विक्रेता अलगाव के मामलों में प्रथा का पालन करते हैं और यदि हां, तो वह रिवाज क्या है?
3. क्या बिक्री विचार के लिए और कानूनी आवश्यकता के लिए की गई थी?
4. क्या इन दावों को सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर लाया गया है?

5. क्या ये दावे विक्रेता की मिलीभगत से किए गए हैं और यदि हां, तो किस प्रभाव से?

ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में मुद्दा नंबर 1 पाया, लेकिन मुद्दा नंबर 2 के तहत यह माना गया कि भूमि वादी के लिए पैतृक नहीं थी। हालांकि यह पाया गया कि पार्टियां प्रथा द्वारा शासित थीं जो आवश्यकता के बिना पैतृक भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती थीं, यह माना गया था कि इसमें शामिल बिक्री आवश्यकता और विचार के लिए थी। शेष दो मुद्दे वादी के पक्ष में पाए गए थे, लेकिन मुद्दों संख्या 2 और 4 पर निष्कर्षों को देखते हुए वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। इसने तीन अपीलों को जन्म दिया, जिन्हें 25 नवंबर, 1970 के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आक्षेपित आदेश द्वारा निपटाया गया था। इस आदेश द्वारा तीनों अपीलों को स्वीकार कर लिया गया। फैसले और आदेशों को रद्द कर दिया गया और वादी को कुछ दस्तावेज पेश करने और प्रतिवादियों को खंडन में सबूत पेश करने का अवसर देने के बाद तीन मामलों को नए सिरे से परीक्षण के लिए भेज दिया गया। इस फैसले के खिलाफ ही याचिकाकर्ताओं ने तीन अलग-अलग अपीलें दायर की हैं, जिनमें 1971 की एस.ए.ओ. संख्या 25, 26 और 29 शामिल हैं। यह फैसला तीनों अपीलों का निपटारा करेगा।

(2) अपीलकर्ताओं की ओर से उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि भले ही अपीलीय अदालत ने पाया था कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ सबूतों को बंद करके गलती की थी, जिन्हें वादी नेतृत्व करना चाहते थे और उस सबूत को अनुमति देने का औचित्य था, फिर भी सभी मुद्दों पर नए फैसले के लिए मामलों को वापस भेजने का कोई अवसर नहीं था। इस संबंध में यह बताया गया था कि वादी द्वारा पेश किए

जाने वाले साक्ष्य केवल मुद्दा संख्या 2 से संबंधित हैं जो संपत्ति की पैतृक प्रकृति से संबंधित है। यह आग्रह किया जाता है कि इस मुद्दे के निर्णय का ट्रायल कोर्ट द्वारा अन्य मुद्दों पर दिए गए निष्कर्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए मामलों को नए निर्णय के लिए वापस भेजने का कोई अवसर नहीं था।

(3) इस तर्क में काफी दम दिखाई देता है। मुद्दा संख्या 2 पर निष्कर्ष निकालने का अन्य मुद्दों के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यहां तक कि अगर यह मुद्दा वादी के पक्ष में पाया जाता है, तो वे मुद्दा संख्या 4 पर निष्कर्षों के मद्देनजर गैर-उपयुक्त होंगे जब तक कि इन निष्कर्षों को अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता है। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी को अतिरिक्त सबूत पेश करने और प्रतिवादियों को उस सबूत का खंडन करने की अनुमति देने के बाद, ट्रायल कोर्ट को मुद्दा नंबर 2 पर फिर से विचार करने का निर्देश देना अधिक उचित और न्यायसंगत था, भले ही विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने किया हो। महसूस किया कि मुद्दा संख्या 2 का परीक्षण उचित नहीं था।

(4) प्रतिवादियों की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी, अर्थात्, अपील समयबद्ध थी। तर्क का आधार यह है कि हालांकि अपील समय के भीतर दायर की गई थी, लेकिन चूंकि कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों को उप रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत समय के भीतर दूर नहीं किया गया था, इसलिए अपील को सीमा की अवधि से परे दायर किया जाना चाहिए। इस तर्क के लिए *बूटा सिंह* बनाम *चांद उर्फ चंदा सिंह से समर्थन मांगा गया है,*[1] जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां

[1] 1970 P.L.R. 803

दिखाई देती हैं: –

"जहां एक अपील सीमा के भीतर दायर की गई थी, जिला न्यायाधीश की अदालत गलत तरीके से क्योंकि उसके पास कोई आर्थिक अधिकार क्षेत्र नहीं था, लेकिन वापसी पर उच्च न्यायालय में फिर से दायर किया गया था, लेकिन अपील के फॉर्म की शुरुआती शीट खाली छोड़ दी गई थी। उच्च न्यायालय कार्यालय द्वारा आपत्ति लिए जाने के बाद फॉर्म को रीफिलिंग के लगभग 6 सप्ताह बाद पूरा किया गया था और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

जहां कोई आवेदन केवल धारा 5 के तहत है, जैसा कि यहां मामला है, धारा 14 के पीछे के सिद्धांत से एकमात्र सहायता यह प्राप्त की जा सकती है कि गलत मंच पर सद्भाव में बिताए गए समय को अपील दायर नहीं करने के लिए उस अवधि की अवधि के लिए पर्याप्त कारण माना जा सकता है, लेकिन पूरी अवधि की गणना नहीं की जा सकती है और अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि की गणना ठीक उसी हद तक और उसी तरह से नहीं की जा सकती है जैसा कि धारा 14 के तहत है क्योंकि वह धारा सीधे लागू नहीं होती है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के नियम 3 के उप-नियम (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक अपील को अपीलकर्ता या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। इस नियम के अनुसार, अपील ज्ञापन का रूप परिशिष्ट जी. संख्या 1 में प्रदान किया

गया है और इस न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड V के अध्याय 1-ए की धारा (ए) में नियम 2 (ए) में इसका संदर्भ है, जो कहता है कि यदि अपील के ज्ञापन के लिए एक मुद्रित फॉर्म निर्धारित किया गया है, उस फॉर्म पर अपील की जाएगी। इसी धारा के नियम '5' में कहा गया है कि उप रजिस्ट्रार सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 3 में निर्दिष्ट कारण के लिए अपील के किसी भी ज्ञापन को उसके द्वारा तय किए गए समय के भीतर संशोधन के लिए वापस कर सकता है और नियम 3 पहले के दो नियमों का पालन न करने के लिए अपील के ज्ञापन की अस्वीकृति या संशोधन से संबंधित है। जिसमें उसी आदेश के नियम 1 का उप-नियम (ए) शामिल है। इसलिए, इन नियमों के अनुसार, उप रजिस्ट्रार के पास प्रतिवादी की प्रत्येक अपील के मामले में, अपील दायर नहीं करने के लिए, अपील के ज्ञापन के रूप में विधिवत और उचित रूप से दायर करने और इसे खाली दर्ज करने की शक्ति थी। कुछ जानकारी, जो स्पष्ट रूप से अन्यथा आवश्यक है, अपील ज्ञापन के लिए मुद्रित रूप में प्रदान की जाती है, और चूंकि फॉर्म को खाली छोड़ दिया गया था, इसलिए जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए , यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें 2 मई, 1969 को प्रतिवादी को अपील वापस कर दी गई थी, जो नियमों के अनुसार नहीं थी, इस मामले का तथ्य यह है कि रिटर्न बहुत हद तक नियमों के अनुसार था। अब अपीलों पर समर्थन से पता चलता है कि आपत्तियां पहली बार 2 मई, 1969 को उठाई गई थीं, और एक सप्ताह के भीतर फिर से दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन यह 9 जून, 1969 तक नहीं किया गया था, जब अपील

ज्ञापन के फॉर्म भरने के संबंध में आवश्यक आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया था। इसलिए उन्हें 11 जून को फिर से लौटा दिया गया, और यह 21 जून, 1969 तक नहीं था, कि आपत्तियों के इस हिस्से का अनुपालन किया गया था। 2 मई से 21 जून, 1969 के बीच की अवधि के लिए, इसे किसी भी तरह से देखने से परिसीमा अधिनियम की धारा **14** लागू नहीं की जा सकती है, और इस अवधि के लिए अपील दायर नहीं करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है।"

(5) ऊपर उठाए गए बिंदु पर विचार करने से पहले, कुछ तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। ये तीनों अपीलें 18 जनवरी, 1971 को दायर की गई थीं और वे सीमा के भीतर थीं। एस.ए.ओ. संख्या 25 और 26 में अपीलों को 21 जनवरी, 1971 को कुछ आपत्तियों को दूर करने के बाद फिर से दाखिल करने के लिए वापस कर दिया गया था, जबकि एसएओ नंबर 29 में इसे 20 जनवरी, 1971 को वापस कर दिया गया था। तीनों मामलों में आपत्तियों में से एक यह थी कि ओपनिंग शीट पूरी नहीं थी। सभी अपीलों को 22 फरवरी, 1971 को फिर से दायर किया गया। 24 फरवरी, 1971 को अपीलों को इस कारण से पुन लौटा दिया गया कि जिस कानून के तहत अपील सक्षम थी, उसे प्रारंभिक पत्र में नहीं बताया गया था। इन अपीलों को 14 अप्रैल, 1971 को पुन दायर किया गया, यद्यपि इन्हें पुन दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। 1971 का एसएओ नंबर 29 15 अप्रैल, 1971 को वापस कर दिया गया और 21 अप्रैल, 1971 को इसे फिर से दायर किया गया।

(6) उपर्युक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों अपीलों में प्रारंभिक पत्रक 14 अप्रैल, 1971 को ही पूरे हुए थे। यद्यपि दो अवसर दिए गए थे, दोनों अवसरों पर

अपीलों को एक सप्ताह की अवधि के बाद लंबे समय के बाद फिर से दायर किया गया था, जिसे इस उद्देश्य के लिए अनुमति दी गई थी। इसलिए अपील ोंं को फिर से दायर करने में इस देरी के प्रभाव का पता लगाया जाना है। क्या यह कहा जा सकता है कि अपील 14 अप्रैल, 1971 को दायर की गई मानी जाएगी जब प्रारंभिक पत्रकों से संबंधित दोष को अंतत या 18 जनवरी, 1971 को दूर कर दिया गया था? यदि यह पाया जाता है कि अपील 18 जनवरी, 1971 को उचित रूप से दायर की गई थी, तो क्या इन अपीलों को अब खारिज कर दिया जा सकता है क्योंकि अपीलकर्ता उप रजिस्ट्रार द्वारा उन्हें दी गई अवधि के भीतर उद्घाटन पत्रकों में दोष को दूर करने में विफल रहे हैं?

उपरोक्त प्रश्न पर विचार करते समय सबसे पहले *बूटा सिंह* के मामले (सुप्रा) में निर्णय का संदर्भ देना होगा , जिस पर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा मुख्य रूप से भरोसा किया गया है। उस मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय में दायर की गई अपीलों को निश्चित रूप से समयबद्ध किया गया था और निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न यह था कि क्या उस अधिनियम की धारा 14 के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण थे। इस संदर्भ में यह माना गया था कि परिसीमा अधिनियम की धारा 14 लागू नहीं हुई थी और देर से अपील दायर करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि *बूटा सिंह* के मामले में देरी का एक हिस्सा डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के देर से अनुपालन के परिणामस्वरूप हुआ था, जिसके द्वारा अपील का ज्ञापन वापस कर दिया गया था। इस देरी को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान ध्यान में रखा गया था कि हलफनामा दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया था समय के भीतर अपील करें। यह सवाल कि अपील

को उस तारीख को दायर किया गया माना जाना चाहिए जब अपील के ज्ञापन में दोष को दूर किया गया था, उस मामले में न तो उठाया गया था और न ही निर्णय लिया गया था। इसलिए, यह प्राधिकरण उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए तर्क को ज्यादा समर्थन नहीं देता है। *नागेंद्र नाथ देव और एक अन्य* वी। *सुरेश चंद्र देव और अन्य*,[2] यह देखा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता में अपील की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय न्यायालय में किसी पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को रद्द करने या संशोधित करने के लिए कोई भी आवेदन इस शब्द की सामान्य स्वीकृति के भीतर एक अपील है और यह अपील से कम नहीं है क्योंकि यह अनियमित या अक्षम है। इस पहलू को छोड़ दें तो आदेश 41 के नियम 1 और 3 और उच्च न्यायालय के नियम और आदेश, खंड 5 के भाग ए (ए) के अध्याय 1 के नियम 5 के साथ नियम 2 (ए) को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में अपील को 14 अप्रैल को दायर नहीं माना जा सकता है। 1971 और इसे समय-सीमा के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है, हालांकि अपील के ज्ञापन ोें को नियम 3 के तहत खारिज किया जा सकता था जब इन्हें प्रस्तुत किया गया था। इस स्तर पर इन नियमों का संदर्भ दिया जाए जो निम्नानुसार हैं -

"ऑर्डर XLI

मूल आदेशों से अपील-

1. *अपील का रूप। ज्ञापन के साथ क्या करना है*- (1) प्रत्येक अपील

[2] A.I.R. 1932 P.C. 165

अपीलकर्ता या उसके वकील द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में पसंद की जाएगी और न्यायालय या ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जिसे वह इस संबंध में नियुक्त करता है। ज्ञापन के साथ उस निर्णय की डिक्री की एक प्रति भी होगी (जब तक कि अपीलीय न्यायालय उसे समाप्त नहीं करता है) जिस पर इसकी स्थापना की गई है।

2. *ज्ञापन की सामग्री* - ज्ञापन बिना किसी तर्क या कथा के अपील की गई डिक्री पर आपत्ति के आधारों को संक्षिप्त रूप से और अलग-अलग शीर्षों के तहत निर्धारित करेगा; और ऐसे आधारों को लगातार क्रमांकित किया जाएगा।

3. *ज्ञापन की अस्वीकृति या संशोधन*- (1) जहां अपील का ज्ञापन पहले से निर्धारित तरीके से तैयार नहीं किया गया है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जा सकता है, अपीलकर्ता को न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर संशोधित करने के उद्देश्य से या तब और वहां संशोधित किया जा सकता है।

4. जहां न्यायालय किसी ज्ञापन को अस्वीकार करता है, वह इस तरह की अस्वीकृति के कारणों को दर्ज करेगा।

5. जहां अपील ज्ञापन में संशोधन किया जाता है, वहां न्यायाधीश, या ऐसा अधिकारी, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करता है, संशोधन पर हस्ताक्षर करेगा या उसे आरंभ करेगा।

पंजाब उच्च न्यायालय के नियम और ऑर्डर

वॉल्यूम V

अध्याय 1

भाग -A -(a)

4. (a) अपील का प्रत्येक ज्ञापन, और प्रत्येक आवेदन अंग्रेजी भाषा में होगा और पानी के निशान वाले सादे कागज पर दोहरी दूरी में टाइप किया जाएगा, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए एक मुद्रित फॉर्म निर्धारित नहीं किया जाता है। इसकी अध्यक्षता "पंजाब उच्च न्यायालय ------- में :(स्थान) पर की जाएगी" और अपीलकर्ता या आवेदक द्वारा या उसकी ओर से उच्च न्यायालय में अभ्यास करने के अधिकार के हकदार वकील द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। मूल टाइप की गई प्रति, न कि कार्बन प्रति, इस न्यायालय में दायर की जाएगी। यदि किसी भी दस्तावेज को डुप्लिकेट में दायर करने की आवश्यकता होती है, तो डुप्लिकेट कॉपी पहली कार्बन कॉपी होगी। किसी भी ज्ञापन या आवेदन या उसकी प्रति पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह पठनीय न हो।

5. डिप्टी रजिस्ट्रार आदेश एक्सएलआई, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 3 में निर्दिष्ट कारण के लिए उनके द्वारा तय किए गए किसी भी अपील ज्ञापन के लिए निर्धारित समय के भीतर संशोधन के लिए वापस कर

सकता है।

आदेश 41 के नियम 1 में प्रावधान है कि प्रत्येक अपील को ज्ञापन के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस नियम के उप-नियम (2) में आगे कहा गया है कि ज्ञापन में क्या कहा जाना चाहिए। इस नियम में मुद्रित प्रपत्र का कोई संदर्भ नहीं है जो उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है या संख्या 1 पर परिशिष्ट जी में उल्लिखित फॉर्म का संदर्भ है, लेकिन संदर्भ केवल उस तरीके का है जिसमें ज्ञापन तैयार किया जाना है। प्रयुक्त अभिव्यक्ति "ज्ञापन के रूप में" है, न कि ज्ञापन के "मुद्रित रूप पर", या, "निर्धारित रूप" पर। आदेश 41 के नियम 1 का उप-नियम (2) यह स्पष्ट करता है कि ज्ञापन में क्या शामिल है। फिर से नियम 3 में यह प्रावधान किया गया है कि अपील के ज्ञापन को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि इसे यहां निर्धारित तरीके से तैयार नहीं किया गया है। "यहां से पहले" पद उप-नियम (2) सहित आदेश 41 के नियम 1 को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि ज्ञापन डिक्री पर आपत्ति के अलग-अलग शीर्षों के तहत संक्षिप्त रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन तर्कपूर्ण या कथात्मक रूप में तैयार किया गया है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जा सकता है क्योंकि इसे पहले निर्धारित तरीके से तैयार नहीं किया गया था। हालांकि, ज्ञापन को नियम 3 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मुद्रित फॉर्म पर तैयार होने में विफल रहा है जैसा कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड 5, अध्याय 1, भाग ए (ए) के नियम 2 (ए) में प्रदान किया गया है, जबकि नियम 3 द्वारा इसकी परिकल्पना नहीं की गई है। यहां तक कि ऊपर उल्लिखित उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के नियम 5 में केवल आदेश 41 के नियम 3 में निर्दिष्ट कारणों को संदर्भित करता है, न कि

इन नियमों के नियम 2 (ए) में उल्लिखित कारणों को।

(8) इस मामले को ध्यान में रखते हुए, मैंने पाया कि अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड V, अध्याय 1, भाग ए (ए) के नियम 2 (ए) में उल्लिखित मुद्रित प्रपत्रों के सभी कॉलम भरने में विफल रहने के लिए नियम 3 के तहत अपील के ज्ञापन को खारिज नहीं किया जा सकता था।

(9) यहां तक कि अगर यह स्वीकार किया जाता है कि समय के भीतर उच्च न्यायालय के नियमों और आदेश खंड 5, अध्याय 1, भाग ए (ए) के नियम 2 (ए) में प्रदान किए गए मुद्रित फॉर्म को भरने में विफलता से दायित्व होगा कि ज्ञापन को आदेश 41 के नियम 3 के तहत अस्वीकार किया जा सकता है, तो यह उत्तरदाताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। यह नियम तब लागू नहीं होगा जब अपील स्वीकार कर ली गई हो और प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन को अस्वीकार नहीं किया गया हो। हालांकि आदेश 41 के नियम 3 में यह विशेष रूप से नहीं कहा गया है कि यदि अपील का ज्ञापन अपीलकर्ता को न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर संशोधित करने के लिए वापस कर दिया जाता है और यदि निर्धारित समय के भीतर संशोधन नहीं किया जाता है, तो अपील को अस्वीकार कर दिया जा सकता है, लेकिन यह शक्ति स्वाभाविक रूप से इस नियम से प्रवाहित होगी। यदि अपील के ज्ञापन को निर्धारित तरीके से तैयार नहीं किए जाने की स्थिति में पहली बार में खारिज किया जा सकता है, तो इसे निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया जा सकता है यदि संशोधन न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है। किसी भी मामले में, यदि ज्ञापन नियम 3 के तहत अस्वीकार नहीं किया गया है। अपील स्वीकार किए जाने के बाद इसे खारिज नहीं किया जा सकता है और इसे नियमित

सुनवाई के लिए निर्धारित करना होगा। मैं *चिंतापाटला वेंकटनरसिम्हा रामचंद्र राव और अन्य*[3] से इस दृष्टिकोण के लिए समर्थन चाहता हूं। उस मामले में एक पक्ष अपील के ज्ञापन को पूरा करने में विफल रहा, भले ही यह उसे तीन बार लौटा दिया गया था और उसे पूर्ण रूप में फिर से पेश करने के लिए हर बार पर्याप्त समय दिया गया था। अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि अपील के ज्ञापन को अस्वीकार या खारिज करना अदालत के लिए खुला नहीं था। अपीलकर्ता के वकील ने *नगिंदर नाथ डे* (2) के मामले से इस तर्क के लिए समर्थन मांगा था , जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। प्रिवी काउंसिल के मामले को इस आधार पर प्रतिष्ठित किया गया था कि उस मामले में अपील स्वीकार कर ली गई थी और उस पर सुनवाई की गई थी, जबकि मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में अपील को स्वीकार नहीं किया गया था। *चिंतापतला के मामले में संदर्भ बिधु* भूषण बख्शी *बनाम* कलाचंद रॉय[4] *का भी था* , जिसमें यह माना गया है कि एक अपील को तब तक अदालत के समक्ष ठीक से नहीं लाया जा सकता है जब तक कि इसे पंजीकृत नहीं किया जाता है। *बिधु भूषण बख्शी* के मामले में विचार को स्वीकार करते हुए, यह देखा गया कि नोटिस के तहत अपील के ज्ञापन को पंजीकृत नहीं किया गया था, जिसे अपील के रूप में नहीं माना जाना था जो अदालत के समक्ष था, बल्कि इसे केवल अपील के ज्ञापन के रूप में माना जाना था जिसे अदालत में प्रस्तुत किया गया था। अपीलकर्ता के वकील की इस दलील को खारिज करते हुए कि यदि आदेश 41 के नियम 3 के तहत अपील के ज्ञापन को खारिज नहीं किया जा सकता है, तो इसे बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता

[3] A.I.R. 1933 Mad. 358
[4] A.I.R. 1927 Cal. 775

है, यह देखा गया-

> "जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इस मामले को एक अपील के रूप में माना जाना चाहिए जिसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है और न ही एक अपील के रूप में जो न्यायालय के समक्ष है। अपील स्वीकार किए जाने से पहले उसे पूरा करना होगा। यह इतना स्पष्ट मामला है कि इसके लिए कोई नियम आवश्यक नहीं है, और मुझे पहले से ही संदर्भित प्रिवी काउंसिल मामले में कुछ भी नहीं मिल सकता है जो इसके विपरीत है।"

अंत में यह देखा गया कि अपील का ज्ञापन पूरा नहीं हुआ था और इसे उचित रूप में रखने के लिए कोई और समय नहीं दिया जा सकता था और परिणामस्वरूप इसे अस्वीकार कर दिया गया था। मद्रास मामले का अनुपात यह है कि यदि कोई अपील स्वीकार नहीं की गई है, तो ज्ञापन को आदेश 41, नियम 3 के तहत अस्वीकार किया जा सकता है, या इस कारण से कि यह रियायत के माध्यम से अनुमत समय के भीतर पूरा नहीं हुआ है। इससे यह आवश्यक रूप से यह माना जाएगा कि यदि अपील स्वीकार कर ली गई है तो ज्ञापन को आदेश 41 के नियम 3 के तहत या किसी अन्य प्रावधान के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है।

(10) अपीलकर्ताओं की ओर से क़रुम और अन्य *बनाम* देवा सिंह और अन्य[5] *का भी संदर्भ दिया गया था,* जिसमें एक पत्र पेटेंट अपील में अपील का ज्ञापन

[5] A.I.R. 1934 Lah. 701

अदालत शुल्क के बिना दायर किया गया था और छुट्टी देने पर अपील के ज्ञापन पर अदालत शुल्क की मुहर तय की गई थी और अपील को तब स्वीकार कर लिया गया था। यह माना गया कि अपील दायर करने में देरी, यदि कोई हो, को माफ कर दिया जाना चाहिए। इस समानता पर यह आग्रह किया गया था कि अपीलों को स्वीकार कर लिया गया है, समय के भीतर अपील ोें के ज्ञापनों को फिर से दाखिल करने में देरी को स्वीकार करने वाले द्वारा माफ कर दिया जाना चाहिए। बेंच। इस तर्क के लिए *रघुनंदन सहाय और अन्य* बनाम राम *सुंदर प्रसाद*[6] *से भी समर्थन मांगा* गया था, जिसमें यह माना गया था कि यदि कोई न्यायालय अपने भुगतान के लिए निर्धारित समय के बाद घाटे की अदालत-शुल्क स्वीकार करता है और वाद दर्ज किया जाता है, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायालय देरी को माफ करता है और विस्तार प्रदान करता है, क्योंकि यदि वह चाहता तो अदालत आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद को खारिज कर सकती थी। जी.आई. का भी उल्लेख किया गया था। *पी. रेलवे कंपनी।* बनाम *राधाकिसान जयकिशन और अन्य*[7]। उस मामले में, अपील के ज्ञापन में कहा गया था कि फैसले की प्रति बाद में दी जाएगी। अपील को प्रस्तुति पर स्वीकार कर लिया गया। यह माना गया था कि यह माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने फैसले की प्रति को हटा दिया।

(11) अंत में अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि जिस दिन कार्यालय द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी, उस दिन अपीलकर्ताओं के वकील को अपील वापस कर दी गई थी और इसलिए, यह कहा जा सकता है कि दोनों अवसरों पर आपत्ति को हटाने के

[6] A.I.R. 1925 Patna 299
[7] A.I.R. 1926 Nagpur 57

लिए अनुमति दी गई एक सप्ताह की अवधि के बाद अपील फिर से दायर की गई थी। इस तर्क में काफी दम है। अपीलों के ज्ञापनों पर यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलकर्ताओं या उनके वकील को सुधार के लिए अपीलें किन तारीखों पर वापस कर दी गई थीं, और इस स्थिति को देखते हुए, यह मानने का कोई अवसर नहीं है कि दोषों को दूर करने के लिए अपील ों को वापस करने के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद फिर से दायर किया गया था।

(12) ऊपर बताए गए कारणों के लिए, मुझे उत्तरदाताओं की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई दम नहीं लगता है। परिणाम यह है कि अपील ों की अनुमति दी जाती है और मामले को नियम 23-ए के बजाय आदेश 41, नियम 25 के तहत इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट पार्टियों को मुद्दे नंबर 2 पर साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर देगा और इस मुद्दे पर निर्णय लेने के बाद अपीलके निर्णय के लिए अपीलीय अदालत को निष्कर्ष के साथ साक्ष्य वापस कर देगा। रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 11 अक्टूबर, 1971 को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के

उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल , हरियाणा